विवरण

1991–92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको द्वारा स्वीकृत रिहायशी एककों के राज्यवार ब्यौरे :–

सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत रिहायशी एकक
1.	आंध्र प्रदेश	1815
2.	आसाम	1825
3.	गुजरात	8573
4.	केरल	9150
5.	कर्नाटक	12019
6.	मेघालय	175
7.	महाराष्ट्र	4667
8.	ओड़ीसा	17000
9.	तमिलनाडु	22000
10.	उत्तर प्रदेश	68486
11.	पश्चिम बंगाल	7440

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में आधारभूत सुविधायें

1486. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और आवास तथा शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में स्थित बहुत से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में बेहतर नागरिक तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार और आवास तथा शहरी विकास निगम ने कौन-कौन सी परियोजनायें आरम्भ की हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई है; और

(घ) वर्ष 1992–93 के दौरान गुजरात में कितनी धनराशि खर्च की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) (क) से (ग) छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के समन्वित विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वर्ष 1979–80 में प्रारम्भ की गई थी। 1979–80 से 31–3–92 तक छोटे और मध्यम दर्जे के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत 517 शहरों को शामिल किया गया है तथा विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को 176.17 रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक हुडको घटक सहित आई डी एस एम टी के संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप उस वित्त वर्ष के दौरान धनराशि की सुलभता के आधार पर समय-समय पर मंजूरी दी जाती है। 1992–93 के दौरान आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत 13 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Pending cases with DDA for Allotment of flats

1487. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:
SHANKER DAVE:
SHANKER DAVE:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the canes which are pending with the Delhi Development